

भारत के राजपत्र असाधारण भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार वनियामक प्राधकरण
अधसूचना

दूरसंचार(प्रसारण एवं केबल) सेवा इंटरकॉनेक्शन (एड्रे सबल सस्टम्स)
(चौथा संशोधन) वनियम, 2022
(2022 का 2)

नई दिल्ली 22/1/2022

फ. नं. आर.जी-1/2(2)/2022-बी और सीएस (2)- भारतीय दूरसंचार वनियामक प्राधकरण अधनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 36 सपठित धारा 11 की उप-धारा (1) के अनुच्छेद (ख) के उप-अनुच्छेद (पप), (पपप) और (पअ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सपठित संचार एवं सूचना प्रोद्योगकी मंत्रालय (दूरसंचार वभाग) में भारत संचार की अधसूचना संख्या 39,

(क) जिसे उक्त अधनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (डी) और धारा 2 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (के) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है, और

(ख) जो भारत के गजट, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3 में अधसूचना संख्या एस.ओ 44 (ई) और 45 (ई) दिनांक 9 जनवरी, 2004 के अंतर्गत प्रकाशित हुई है,-

भारतीय दूरसंचार वनियामक प्राधकरण, दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा इंटरकॉनेक्शन (एड्रे सबल सस्टम्स) वनियम, 2017 (2017 का 1) में आगे संशोधन करने के लिए एतद द्वारा निम्न वनियमों का निर्माण करता है, अर्थात्-

1. (1) इन वनियमों को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा इंटरकॉनेक्शन (एड्रे सबल सस्टम) (चौथा संशोधन) वनियमों, 2022 (2022 का 2)
(2) वे सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा इंटरकॉनेक्शन (एड्रे सबल सस्टम) वनियम, 2017 (जिसे यहां पर "मुख्य वनियमों" के रूप में संदर्भित किया गया है) अर्थात्:

"(4) कसी प्रसारक को टेली वजन चैनलों के वतरकों को पे चैनल या पे चैनलों के बुके के अधिकतम खुदरा मूल्य पर, अधिकतम खुदरा मूल्य के पंद्रह प्रतिशत से अधिक छूट की पेशकश करने की अनुमति होगी:

बशर्ते कि कसी ब्रॉडकास्टर द्वारा उप-वनियम (3) के तहत घोषित वतरण शुल्क और इस उप-वनियम के तहत दी जाने वाली छूट की राशि कसी भी मामले में पे चैनल या पे चैनलों के बुके के अधिकतम खुदरा मूल्य के पैंतीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जैसा भी मामला हो।

बशर्ते कि टेली वजन चैनलों के वतरकों के लिए छूट की पेशकश, यदि कोई हो, चैनल के संयुक्त सब्सक्रिप्शन पर आधारित होगी, बुके के साथ-साथ अ-ला-कार्ट दोनों में, और इस तरह की छूट, अ-ला-कार्ट और (कसी भी) बुके के हिस्से के रूप में ऐसे चैनल से राजस्व यदि कोई हो, आनुपातिक आधार पर पेश की जाएगी :

स्पष्टीकरण: कसी प्रसारक द्वारा पे चैनल या बुके के अ धकतम खुदरा मूल्य पर प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली कोई भी छूट, अ-ला-कार्टे के साथ-साथ बुके में भी सब्सक्राइबर्स की वास्तविक संख्या या एक महीने में दर्ज वास्तविक सब्सक्रिप्शन प्रतिशत के आधार पर, चैनल की कुल सब्सक्रिप्शन दोनों को ध्यान में रखा जाएगा।

ट्याबल

(क) मान लें कि एक ब्रॉडकास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को पे चैनल के अ धकतम खुदरा मूल्य पर 10% की छूट के रूप में प्रोत्साहन के रूप में दे रहा है, यदि उस चैनल का वास्तविक सब्सक्रिप्शन प्रतिशत 75% तक पहुंच जाता है। यदि उस चैनल का वास्तविक सब्सक्रिप्शन प्रतिशत अ-ला-कार्टे आधार पर 30% और बुके में 45% तक पहुंच जाता है, तो वतरक को उपरोक्त छूट प्राप्त करने के लिए पात्र होना चाहिए, क्योंकि उस चैनल का वास्तविक संयुक्त सब्सक्रिप्शन प्रतिशत 75% होगा।

(ख) मान लें कि एक ब्रॉडकास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को एक पे चैनल (चैनल एक्स) के अ धकतम खुदरा मूल्य पर 10% की प्रोत्साहन के रूप में छूट की पेशकश कर रहा है, यदि उस चैनल का वास्तविक संयुक्त सब्सक्रिप्शन प्रतिशत अ-ला-कार्टे आधार पर है और एक बुके के हिस्से के रूप में 75% हैं। अब, मान लें कि उस चैनल का वास्तविक सब्सक्रिप्शन प्रतिशत अ-ला-कार्टे में 30% और बुके के हिस्से के रूप में 45% तक पहुंच जाता है, तो वतरक को उपरोक्त छूट प्राप्त करने का पात्र होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक संयुक्त सब्सक्रिप्शन प्रतिशत चैनल 75% होगा। ऐसे मामले में, प्राप्त की गई संयुक्त सदस्यता के लिए प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली छूट की गणना अ-ला-कार्टे आधार पर चैनल के राजस्व के अनुपात में और बुके में, यानी अ धकतम खुदरा मूल्य और 'प्रभावी' के आधार पर की जाएगी। चैनल की कीमत मान लें कि बुके को कुछ चैनलों को मिलाकर डिजाइन किया गया है और उस बुके का हिस्सा बनने वाले अलग-अलग चैनलों के अ-ला-कार्टे मूल्य के योग में 40% की कमी की पेशकश की गई है। जैसे चैनल एक्स का अ धकतम खुदरा मूल्य 10/- रुपये है, तो ऐसे मामले में चैनल जिन बुके का 'प्रभावी मूल्य' 6/- रुपये होगा (अर्थात् टेली वजन चैनल के अ धकतम खुदरा मूल्य से 40% कम)। इस चैनल एक्स के लिए प्रोत्साहन की अंतिम राशि नीचे दी गई है:

अ-ला-कार्टे आधार पर और बुके के हिस्से के रूप में चैनल एक्स के आनुपातिक राजस्व का योग = अ धकतम खुदरा मूल्य x अ-ला-कार्टे आधार पर सब्सक्रिप्शन + बुके में प्रभावी मूल्य x बुके का सब्सक्रिप्शन

चैनल एक्स पर छूट की राशि = अ-ला-कार्टे आधार पर और बुके के हिस्से के रूप में चैनल एक्स के आनुपातिक राजस्व का योग x निर्धारित % छूट

(ग) मान लें कि एक ब्रॉडकास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को पे चैनल के अ धकतम खुदरा मूल्य पर 10% की छूट के रूप में प्रोत्साहन के रूप में दे रहा है, यदि उस चैनल का वास्तविक संयुक्त सब्सक्रिप्शन प्रतिशत 75% हो जाता है। अब, मान लें कि चैनल को अ-ला-कार्टे आधार पर और दो बुके के हिस्से के रूप में भी पेश किया जाता है, और इसकी वास्तविक सदस्यता प्रतिशत अ-ला-कार्टे में 10%, बुके ए के हिस्से के रूप में 20% और बुके बी के हिस्से के रूप में 45% है। ऐसे मामले में, प्राप्त संयुक्त सदस्यता के लिए प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली छूट की गणना अ-ला-कार्टे के साथ-साथ प्रत्येक बुके में चैनल के राजस्व के अनुपात में की जाएगी। मान लें कि बुके ए और बुके बी को कुछ चैनलों को मिलाकर डिजाइन किया गया है और क्रमशः उस बुके का हिस्सा बनने वाले अलग-अलग चैनलों के अ-ला-कार्टे मूल्य के योग में 40% और 30% की कटौती की पेशकश की गई है। जैसे, चैनल एक्स का अ धकतम खुदरा मूल्य 10/- रुपये है तो ऐसे मामले में बुके ए में चैनल X का 'प्रभावी मूल्य'

6/- रुपये होगा (अर्थात टेली वजन चैनल के अधिकतम खुदरा मूल्य से 40% कम) और बुके बी में 7/- रुपये होगा (यानी टेली वजन चैनल के अधिकतम खुदरा मूल्य से 30% कम)। इस मामले में, इस चैनल X के लिए प्रोत्साहन राश की अंतिम राश निम्नानुसार निकाली जाएगी:

अ-ला-कार्टे आधार पर और बुके के हिस्से के रूप में चैनल के आनुपातिक राजस्व का योग = अधिकतम खुदरा मूल्य x अ-ला-कार्टे आधार पर सदस्यता + बुके ए में प्रभावी मूल्य x बुके ए की सदस्यता + बुके बी में प्रभावी मूल्य x बुके बी की सदस्यता

उक्त टेली वजन चैनल की छूट की राश = अ-ला-कार्टे आधार पर और बुके के हिस्से के रूप में टेली वजन चैनल के आनुपातिक राजस्व का योग x निर्धारित % छूट।

बशर्ते यह भी कि टेली वजन चैनलों के वतरकों को छूट की पेशकश, यदि कोई हो, निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण शर्तों के आधार पर होगी:

बशर्ते यह भी कि छूट के पैरामीटर मापने योग्य और संगणनीय होंगे।"

3. मूल वनियमों के वनियम 10 में, उप-वनियम (12) के स्पष्टीकरण के लिए, निम्न लखत स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण: कोई संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी महीने में दर्ज की गई उपभोक्ताओं की वास्तविक संख्या या वास्तविक सब्सक्रिप्शन प्रतिशत पर आधारित पे चैनल या पे चैनलों के बुके के अधिकतम खुदरा मूल्य पर किसी प्रसारक द्वारा प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की गई किसी छूट को अपने चैनल के लिए कोई न्यूनतम उपभोक्ता आधार या सब्सक्रिप्शन प्रतिशत के लिए गारंटी नहीं मन जाएगा।"

(वी. रघुनंदन)
सचिव, भादु वप्रा

नोट.1---- मूल वनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 21-4/2016-बी एंड सीएस दिनांक 3 मार्च, 2017 (2017 का 1) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

टिप्पणी। 2---- मूल वनियमों को अधिसूचना संख्या 21-6/2019-बी एंड सीएस दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 (2019 का 7) द्वारा संशोधित किया गया था।

टिप्पणी। 3---- अधिसूचना संख्या 21-5/2019-बी एंड सीएस दिनांक 1 जनवरी 2020 (2020 का 1) द्वारा मूल वनियमों में और संशोधन किया गया।

टिप्पणी। 4---- अ धसूचना संख्या आरजी-1/2/(3)/2021-बी और सीएस(2) दिनांक 11 जून 2021 (2021 का 1) द्वारा मूल वनियमों में और संशोधन कया गया।

टिप्पणी। 5----व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एट्रेसेबल सस्टम्स) (चौथा संशोधन) वनियम, 2022 (2022 का 2) के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।
प्रसारकों द्वारा डीपीओ को दी जाने वाली अतिरिक्त छूट

1. डिजिटल एड्रसेबल सस्टम (डीएस) के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए और इस क्षेत्र को इसके लाभों का एहसास कराने में सक्षम बनाने के लिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने उचित परामर्श प्रक्रिया के बाद, डिजिटल एड्रसेबल सस्टम के लिए एक 'नया नियामक ढांचा' प्रकाशित किया। 3 मार्च 2017 को। इस ढांचे में दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रसेबल सस्टम) वनियम, 2017, दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रसेबल सस्टम) वनियम, 2017 के मानक शामिल हैं। डिजिटल एड्रसेबल सस्टम के माध्यम से टेली वजन से संबंधित प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रसेबल सस्टम) टैरिफ ऑर्डर, 2017। नए नियामक ढांचे को मार्च 2017 में अधिसूचित किया गया था। हालांकि, उक्त वनियमों की कानूनी चुनौतियों के अनुसार, नियमों को 3 जुलाई 2018 को अधिसूचित किया गया था और कानूनी घोषणाओं को संतुष्ट करने के बाद 29 दिसंबर 2018 से प्रभावी हुआ।

2. इस ढांचे ने टेली वजन वतरण मूल्य श्रृंखला में आमूल-चूल परिवर्तन किया। सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता, गैर-भेदभाव और राजस्व आश्वासन नए ढांचे के अंतर्निहित सद्घांत थे। ढांचे ने उपभोक्ताओं को अपने सबस्क्राइब्ड चैनलों पर पूर्ण नियंत्रण के साथ सक्षम किया जैसे पहले कभी नहीं किया था।

3. नए नियामक ढांचे 2017 के लागू होने के बाद, ट्राई ने जुलाई और अगस्त 2019 में एक उपभोक्ता सर्वेक्षण किया। ट्राई ने उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाली कुछ कमियों को देखा। काफी कुछ उपभोक्ता अभ्यावेदन भी थे। जैसे-जैसे नए नियामक ढांचे ने कुछ व्यावसायिक नियमों को बदला, कई सकारात्मक बातें सामने आईं। उपभोक्ता अपनी पसंद का प्रयोग कर सकते हैं जैसे पहले कभी नहीं किया। मूल्य श्रृंखला में हितधारकों को उनके राजस्व शेयरों का आश्वासन दिया गया था। तीसरे पक्ष के सूचीबद्ध लेखापरीक्षकों के माध्यम से विश्वास-आधारित लेखापरीक्षा व्यवस्था ने काम करना शुरू कर दिया। इन उपायों से प्रसारण क्षेत्र में व्यवस्थित विकास संभव हुआ। फिर भी, यह देखा गया कि कुछ सेवा प्रदाता अपने फायदे के लिए ढांचे के उपलब्ध लचीलेपन का फायदा उठा रहे थे। प्राधिकरण ने इन मुद्दों के समाधान के लिए एक परामर्शी अभ्यास किया। हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद, ट्राई ने 1 जनवरी 2020 को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2017 में संशोधन करके संशोधित रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2020 को अधिसूचित किया।

4. ट्राई ने 7 मई 2022 को प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए नए नियामक ढांचे से संबंधित मुद्दों पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया। कृपया इस परामर्श पत्र और दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाओं (आठवें) (पता योग्य) के लिए व्याख्यात्मक ज्ञापन देखें। सस्टम टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2022 (2022 का 4) उन घटनाक्रमों से संबंधित ववरणों के लिए जिनके कारण उक्त परामर्श पत्र दिनांक 7 मई 2022 निकला।

5. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और इन-हाउस विश्लेषण पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रसेबल सस्टम) (चौथा संशोधन) वनियम, 2022 को अंतिम रूप दिया है (इसके बाद "चौथा संशोधन" के रूप में संदर्भित) संशोधन वनियम")। बाद के पैराग्राफ चौथे संशोधन वनियमों की वस्तुओं और कारणों की व्याख्या करते हैं।
प्रसारकों द्वारा डीपीओ को दी जाने वाली अतिरिक्त छूट

6. 7 मई 2022 के 'प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए नए नियामक ढांचे से संबंधित मुद्दे' पर परामर्श पत्र में परामर्श के लिए एक मुद्दा इस प्रकार था:

'प्रश्न 6। क्या प्रसारकों द्वारा डीपीओ को प्रदान किए जाने वाले अ-ला-कार्टे चैनलों के एमआरपी और चैनलों के बुके पर वतरण शुल्क के अतिरिक्त कोई छूट होनी चाहिए? यदि हां, तो ऐसी छूट प्रदान करने के लिए राश और नियम व शर्तें क्या होनी चाहिए? कृपया अपनी टिप्पणियों को औचित्य के साथ प्रदान करें।

7. प्रति क्रिया में, कई हितधारकों ने डीपीओ को प्रसारकों द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट का समर्थन किया। इनमें से कई हितधारकों ने कहा कि प्रसारकों/वतरकों द्वारा दी जाने वाली छूट सब्सक्राइबर के लिए फायदेमंद है, जो कम दरों पर सामग्री की अधिक वधता का आनंद लेते हैं। उपभोक्ता की पसंद बुके के पक्ष में है, और इस लिए, बुके पर दी जा रही छूट को रोकने का कोई उचित औचित्य नहीं है। इसके अलावा, उस छूट की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए जो ब्रॉडकास्टर अ-ला-कार्टे और बुके के एमआरपी पर डीपीओ को दे सकते हैं। डीपीओ के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की छूट महत्वपूर्ण बाजार उपकरण हैं। हितधारकों ने राय दी कि छूट और कमीशन पर एक सहनशीलता मॉडल को लागू करने का समय आ गया है। एनटीओ 1 में यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल हैं कि छूट और कमीशन गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर पेश किए जाते हैं और इस तरह, किसी अतिरिक्त शर्त की आवश्यकता नहीं है। छूट के पक्ष में दिया गया एक और तर्क यह था कि अलग-अलग लक्ष्य बाजारों में या नए उत्पाद लॉन्च के लिए अलग-अलग छूट देने की आवश्यकता हो सकती है। इस लिए, जब इस तरह की छूट मापने योग्य मापदंडों पर बिना किसी भेदभाव के समता के आधार पर पेश की जाती है, तो ऐसी छूट प्रोत्साहन व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से दिए जाने चाहिए।

8. एक हितधारक की राय थी कि छोटे प्रसारकों को वधन लक्ष्य बाजारों तक पहुंचने और ब्रॉडकास्टर के ग्राहक आधार का विस्तार करने के लिए कुशल डीपीओ को प्रोत्साहित करने/सुरक्षित करने के लिए उनकी व्यावसायिक रणनीति के अनुसार डीपीओ को और छूट देने की अनुमति दी जानी चाहिए। एक अन्य हितधारक ने राय दी कि 20% के अनिवार्य न्यूनतम वतरण शुल्क के अलावा 15% तक की छूट देने की मौजूदा प्रथा को जारी रखा जाना चाहिए और चूंकि छूट के अंतिम लाभार्थी उपभोक्ता हैं, ट्राई को बुके पर भी छूट की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से है उपभोक्ताओं के लिए अधिक बेहतर।

9. एक हितधारक ने राय दी कि प्रसारकों को डीपीओ को प्रसारकों द्वारा प्रस्तावित एमआरपी पर 35% की छूट (वतरण शुल्क + प्रोत्साहन) प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एक अन्य हितधारक ने राय दी कि अतिरिक्त 15% का प्रावधान बिना किसी राइडर के जारी रखा जा सकता है जो ब्रॉडकास्टर के लिए ववेकाधीन है और ब्रॉडकास्टर द्वारा डीपीओ को दी जाने वाली कुल छूट को 35% पर तय किया जाना चाहिए। एक हितधारक ने राय दी कि छूट के 15% स्लैब को हटा दिया जाना चाहिए और प्रसारकों को अ-ला-कार्टे चैनलों पर छूट की पेशकश करने के लिए खुली छूट दी जानी चाहिए, लेकिन दी जाने वाली छूट सभी डीपीओ और ग्राहकों के लिए गैर-भेदभावपूर्ण होनी चाहिए, चाहे अ-ला-ला-कार्टे -कार्टे या गुलदस्ता।

10. दूसरी ओर, हितधारकों का एक अन्य समूह छूट के पक्ष में नहीं था। कई हितधारकों ने राय दी कि ब्रॉडकास्टरों द्वारा अ-ला-कार्टे के साथ-साथ बुके की पेशकश दोनों पर वतरण शुल्क को एमआरपी के 35% पर फ्लैट किया जाना चाहिए, ताकि प्रसारकों द्वारा वरोधी नियामक गति वधियों पर अंकुश लगाया जा सके। यह सुनिश्चित करेगा कि ब्रॉडकास्टर द्वारा निर्धारित अनुचित पैठ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए डीपीओ पर कोई दबाव न डाला जाए। इसके अलावा समता पर, ब्रॉडकास्टर और डीपीओ दोनों को उनके बुके की पेशकश पर अधिकतम 33% की छूट भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एक अन्य सुझाव प्राप्त हुआ कि यह भी अनिवार्य किया जाए कि डीपीओ के साथ इंटरकनेक्ट समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी प्रसारकों को भी डीपीओ के कैरेज रियों पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने चाहिए।

11. कुछ हितधारकों ने कहा कि आज का 20% निश्चित और 15% परिवर्तनीय मार्जिन का अनुपात बहुत ही असंतुलित और ववेकाधीन है और एक बहुत ही सीधे सामग्री मालक/सामग्री वतरक संबंध में बातचीत, ववाद

और मुकदमेबाजी का मूल कारण है। प्रोत्साहन 35% की दर से निश्चित प्रकृति का होना चाहिए, बैंड वड्थ और लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने वाले पार्टनर के लए उचित हिस्सा। 35% से अधिक प्रोत्साहन की कसी भी कम एकल अंक प्रतिशत परिवर्तनीय मात्रा का प्रस्ताव होने पर, प्रसारकों को प्रोत्साहन देने के लए मानदंड के रूप में 'पहुंच' का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कम मात्रा में प्रोत्साहन की अनुमति देने के लए वैकल्पिक प्रस्तावत शीर्ष हो सकते हैं: ए) ब्रॉडकास्टर्स को सब्सक्राइबर रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना, बी) समय पर भुगतान, सी) अनिवार्य श्रवण सब मशन का अनुपालन, आदि। परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त एक सुझाव यह था क छूट चैनलों की पैठ से जोड़ने के बजाय इंटरकनेक्ट वनियमों की कुछ शर्तों के अनुपालन पर डीपीओ को चैनल के एमआरपी पर 15% की छूट दी जानी चाहिए। कुछ एमएसओ की राय थी क ब्रॉडकास्टर्स द्वारा अ-ला-कार्ट के साथ-साथ बुके की पेशकश दोनों पर वतरण शुल्क को एमआरपी के 35% पर फ्लैट कया जाना चाहिए, ता क ब्रॉडकास्टर्स द्वारा ऐसी वरोधी नियामक गति व धर्यों पर अंकुश लगाया जा सके। वैकल्पिक रूप से, प्रसारकों को नियत तारीख पर या उससे पहले एमएसआर रिपोर्ट जमा करने, अनिवार्य ऑ डट के अनुपालन या ऐसे कसी भी पैरामीटर जो नए नियामक ढांचे के सार के अनुरूप हैं, जैसे प्रावधानों पर छूट की पेशकश करने की अनुमति दी जा सकती है। एक हितधारक ने कहा क कसी भी अतिरिक्त छूट की पेशकश नहीं की जानी चाहिए, हालां क, अगर कसी भी तरह की छूट की पेशकश की जानी है, तो यह वश्वास करते हुए क इसे डीपीओ द्वारा अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाएगा, तो इस तरह की छूट की मात्रा के बारे में निर्णय लया जाएगा। ब्रॉडकास्टर प्रचलत बाजार स्थितियों पर वचार कर रहा है।

12. एक संघ ने राय दी क कुल वतरण शुल्क को 35% अनिवार्य कया जाना चाहिए जिसमें 25% एलसीओ के साथ साझा कया जाना चाहिए और 10% एमएसओ द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए। यह इस शर्त पर है क <200चैनल>200 चैनलों के लए एनसीएफ की सीमा 130 और 160 पर निर्दिष्ट के अनुसार बनी रहेगी।

13. एक हितधारक ने कहा क ट्राई को मध्यस्थों के बीच संबंध के नियमन में शा मल होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल सुवधाकर्ता के लए है। इसे उनके बीच ट्राई के साथ छोड़ देना चाहिए, केवल एक सूत्रधार होना चाहिए। ट्राई को लास्ट माइल प्राइ संग रेगुलेशन यानी ब्रॉडकास्टरस र्वस प्रोवाइडर्स और एंड कस्टमर के बीच ध्यान देना चाहिए। एक अन्य हितधारक ने राय दी क बुके और अ-ला-कार्ट चैनलों के एमआरपी पर छूट होनी चाहिए या नहीं, यह ब्रॉडकास्टर्स और डीपीओ द्वारा लया जाने वाला व्यावसायिक निर्णय होना चाहिए न क ट्राई द्वारा लगाया जाने वाला कोई नियम। एक अन्य हितधारक ने यह भी सुझाव दिया क छूट की अधिकतम सीमा निर्धारित करना बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

विश्लेषण

14. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसिबल सिस्टम) विनियम, 2017 दिनांक 3 मार्च 2017 (इसके बाद "इंटरकनेक्शन वनियमन 2017" कहा जाएगा) के विनियम 7 के उप-विनियम 4 के अनुसार, एक प्रसारक को वतरण शुल्क के अतिरिक्त डीपीओ को पे चैनल या पे चैनलों के बुके के एमआरपी पर अधिकतम 15% की छूट देने की अनुमति है। विनियम 7 का उप-विनियम 4 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"(4) कसी प्रसारक को टेली वजन चैनलों के वतरकों को पे चैनल या पे चैनलों के बुके के अ धकतम खुदरा मूल्य पर छूट की पेशकश करने की अनुमति होगी, जो अ धकतम खुदरा मूल्य के पंद्रह प्रतिशत से अ धक नहीं होगी:

बशर्ते कि किसी प्रसारक द्वारा उप-विनियम (3) के तहत घोषित वितरण शुल्क और इस उप-विनियम के तहत दी जाने वाली छूट किसी भी मामले में पे चैनल या पे चैनलों के बुके के अधिकतम खुदरा मूल्य के पैंतीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जैसा भी मामला हो :

बशर्ते कि टेलीविजन चैनलों के वितरकों को छूट की पेशकश, यदि कोई हो, उचित, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण शर्तों के आधार पर होगी:

बशर्ते यह भी कि छूट के मानदंड मापने योग्य और संगणनीय होंगे।"

15. इस संबंध में, इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के विनियम 10 के उप-विनियम 12 को भी नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है, एक प्रसारक को किसी भी प्रावधान को शामिल करने से रोकता है, जिसके लिए डीपीओ को अपने चैनलों के लिए न्यूनतम सब्सक्राइबर बेस या न्यूनतम सब्सक्रिप्शन प्रतिशत का आश्वासन देना होगा:

"(12) एक प्रसारक टेली वजन चैनलों के वतरक के साथ अपने इंटरकनेक्शन समझौते में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रावधान शामिल नहीं करेगा जिसके लए टेली वजन चैनलों के ऐसे वतरक को प्रसारक द्वारा पेश किए गए चैनलों के लए सब्सक्राइबर बेस या न्यूनतम सब्सक्रिप्शन प्रतिशत की गारंटी देने की आवश्यकता होती है और इसके वपरीत कोई भी समझौता शून्य होगा।

स्पष्टीकरण: शंका निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि कसी प्रसारक द्वारा पे चैनल या पे चैनलों के बुके के अ धकतम खुदरा मूल्य पर प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली कोई छूट, सब्सक्राइबर्स की वास्तविक संख्या या वास्तविक सब्सक्रिप्शन प्रतिशत के आधार पर, एक महीने में रिकॉर्ड किए गए न्यूनतम सब्सक्राइबर बेस या इसके चैनल के लए न्यूनतम सब्सक्रिप्शन प्रतिशत की गारंटी नहीं होगी।"

16. नए विनियामक ढांचे 2017 के कार्यान्वयन के दौरान, प्राधिकरण ने देखा कि कुछ प्रसारक डीपीओ को पे चैनलों के बुके के कुछ न्यूनतम सब्सक्रिप्शन की सब्सक्रिप्शन पर ही प्रोत्साहन के रूप में 15% की छूट दे रहे थे। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि प्रसारकों द्वारा डीपीओ को बुके पर प्रवेश-आधारित प्रोत्साहन की पेशकश, प्रवेश-आधारित प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए डीपीओ द्वारा उपभोक्ताओं को बुके को आगे बढ़ा सकती है। यह दृष्टिकोण उपभोक्ता की पसंद को या तो उसकी पसंद के अनुसार बुके या अला-कार्ट चैनल स्वीकार करने के लए बढ़ावा देने के नए विनियामक ढांचे के मुख्य उद्देश्यों में से एक को पराजित कर रहा।
17. तदनुसार, विनियम 7 के उप-विनियम 4 में संशोधन किया गया था ताकि प्रसारकों द्वारा डीपीओ को केवल अला-कार्ट पे चैनलों के एमआरपी पर 15% की छूट की पेशकश की जा सके। तदनुसार इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के विनियम 10 के उप-विनियम 12 में भी संशोधन किया गया था।

18. जैसा क 7 मई 2022 को प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लए नए नियामक ढांचे से संबंधित मुद्दों पर सीपी में उल्लेख किया गया है, चर्चा के दौरान डीपीओ के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया क प्रसारकों को पे चैनलों के बुके पर भी डीपीओ को अतिरिक्त पंद्रह (15%) प्रतिशत छूट देने की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसा क अ-ला-कार्टे चैनलों के लए अनुमति दी गई है।
19. प्रोत्साहन व्यक्तियों को अधिक कुशलता से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। इज़राइली अर्थशास्त्री विकटर लेवी ने इज़राइल में सावधानीपूर्वक तैयार किए गए दो कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया और छात्र-शिक्षक प्रदर्शन में महत्वपूर्ण लाभ पाया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला क, "प्रदर्शन के लए भुगतान प्रोत्साहन शिक्षकों के प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं"। लेखक माइकल आर्मस्ट्रांग पारदर्शी पुरस्कृत निर्णयों का सुझाव देते हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं क कैसे पुरस्कृत प्रक्रियाएं व्यक्ति के प्रदर्शन पर प्रभाव डालती हैं। आधिकारिक वेतन नीतियां और सिद्धांत जो सभी कर्मचारियों के लिए दृश्यमान हैं, इस भावना को बढ़ाएंगे कि पुरस्कृत करना उचित है और इस प्रकार कर्मचारियों की संतुष्टि में वृद्धि होगी। रेजिस टेरपेंड और डेनियल आर. क्रॉस अपने पेपर में अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी, बाजार-आधारित प्रोत्साहनों के बारे में बात करते हैं जो आपूर्तिकर्ताओं को इस आधार पर पुरस्कृत करते हैं कि वे अन्य आपूर्तिकर्ताओं के सापेक्ष कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अपने पेपर में, वे अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख करते हैं कि खरीद के लिए वितरण, गुणवत्ता, नवाचार और लचीलेपन में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन एक प्रभावी दृष्टिकोण हो सकता है, जहां खरीदार-आपूर्तिकर्ता संबंध पारस्परिक निर्भरता की संतुलित और मध्यम मात्रा की विशेषता है।
20. इंटरकनेक्शन रेगुलेशन 2017 के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 77 में बताया गया है कि एक व्यवसाय में, किसी उत्पाद/सेवा की एमआरपी पर छूट आपूर्तिकर्ताओं को मूल्य श्रृंखला में दक्षता में सुधार करके अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए लचीलापन प्रदान करती है। दूसरी ओर बहुत उच्च स्तर की छूट भेदभाव का स्रोत और उपभोक्ताओं के शोषण का स्रोत बन सकती है। अतीत में यह देखा गया था कि कई बार सेवा प्रदाता अपने आरआईओ में अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए बहुत अधिक दरों की घोषणा करते हैं और फिर वे ऐसी दरों पर भारी छूट की पेशकश करते हैं। छूट की अनुचित मात्रा भ्रमपूर्ण/विकृत मूल्य निर्धारण और गैर-स्तरीय प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाती है। प्राधिकरण ने छूट पर एक उचित सीमा लगाना आवश्यक महसूस किया क्योंकि इस तरह के नुस्खे के अभाव में विभिन्न हितधारकों के व्यावसायिक हितों में बाधा आएगी और सब्सक्राइबर्स की पसंद के लिए हानिकारक होगा। इसलिए, इस तरह की छूट को विनियमित करने की आवश्यकता है ताकि इसे पारदर्शी, मापने योग्य और गैर-भेदभावपूर्ण शर्तों पर प्रदान किया जा सके। इसके अलावा, प्राधिकरण कुछ प्रसारकों के विचारों से सहमत है कि आरआईओ में घोषित कीमतों पर अधिकतम छूट की सीमा तय की जानी चाहिए। इससे उनकी सेवाओं के लिए इष्टतम मूल्य घोषित करने में मदद मिलेगी, यानी वह मूल्य जिस पर उनका सकल राजस्व अधिकतम होता है। इससे समान रूप से रखे गए सेवा प्रदाताओं के बीच भेदभाव की संभावना भी कम होगी। 2017 में परामर्श प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितधारकों द्वारा सुझाई गई छूट की सीमा 33% से 50% तक भिन्न थी। इसलिए, प्राधिकरण का विचार था कि डीपीओ को दी जाने वाली वितरण शुल्क और छूट की राशि एमआरपी के 35% तक सीमित होगी। इसके अलावा, विनियमों में यह प्रावधान किया गया है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और

गैर-भेदभावपूर्ण शर्तों के आधार पर आरआईओ में ऐसी किसी भी छूट की पेशकश की जानी चाहिए और छूट के मानदंड मापने योग्य और संगणनीय होने चाहिए।

21. वर्तमान परामर्श प्रक्रिया में, प्राधिकरण को विविध टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। इसका विवरण पूर्व पैरा में देखा जा सकता है। प्राधिकरण का विचार है कि किसी उत्पाद/सेवा के एमआरपी पर छूट मूल्य श्रृंखला में दक्षता में सुधार करने में सहायता करती है। हालांकि, बहुत उच्च स्तर की छूट भेदभाव का स्रोत और उपभोक्ताओं के शोषण का स्रोत बन सकती है। छूट की अनुचित मात्रा भ्रमपूर्ण/विकृत मूल्य निर्धारण और गैर-स्तरीय खेल मैदान की ओर ले जाती है। इसलिए, प्राधिकरण का मानना है कि प्रसारकों को छूट की पेशकश करने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि, इन छूटों पर एक सीमा होनी चाहिए। इसके अलावा, प्राधिकरण का विचार है कि ऐसी किसी भी छूट को उचित, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण शर्तों के आधार पर आरआईओ में पेश किया जाना चाहिए और छूट के मानदंड मापने योग्य और संगणनीय होने चाहिए। परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त सुझावों में से एक यह था कि बुके और अ-ला-कार्टे चैनलों के एमआरपी पर छूट होनी चाहिए या नहीं, यह ब्रॉडकास्टर्स और डीपीओ द्वारा लिया गया व्यावसायिक निर्णय होना चाहिए, न कि भादू वप्रा द्वारा लागू किया जाने वाला कोई नियम। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कानून द्वारा प्राधिकरण को व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करते हुए आदेश दिया गया है। प्रभावी प्रतिस्पर्धा और सब्सक्राइबर्स की पसंद से समझौता करने वाली प्रथाओं पर लगाम लगाना अनिवार्य है। इसलिए, ऐसी छूटों को विनियमित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उचित हैं और पारदर्शी, मापने योग्य और गैर-भेदभावपूर्ण शर्तों पर प्रदान की जाती हैं।
22. नए विनियामक ढांचे के मुख्य उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को उनके भुगतान के लिए सबसे अधिक मूल्य मिले। अ-ला-कार्टे चैनलों या बुके के सब्सक्रिप्शन को बढ़ावा देने के लिए भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को हटाने के लिए और अंतिम उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के चैनलों की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए उचित अवसर प्रदान करने के लिए चाहे वह बुके में हो या अ-ला-कार्टे आधार पर, प्राधिकरण का विचार है कि प्रसारकों को अ-ला-कार्टे चैनलों के साथ-साथ बुके दोनों पर डीपीओ को छूट प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है। यह उम्मीद की जाती है कि इन छूटों का लाभ उपभोक्ताओं को कम दरों पर सामग्री की अधिक विविधता के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा, प्राधिकरण ने इस विनियम में अनिवार्य किया है कि प्रसारक द्वारा पे चैनल या बुके के अधिकतम खुदरा मूल्य पर प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली कोई भी छूट, सब्सक्राइबर्स की वास्तविक संख्या या वास्तविक सब्सक्रिप्शन प्रतिशत के आधार पर, एक महीने में दर्ज, अ-ला-कार्टे और बुके दोनों में चैनल की कुल सब्सक्रिप्शन को ध्यान में रखा जाएगा, यानी ग्राहकों की वास्तविक संख्या या एक महीने में दर्ज वास्तविक सदस्यता प्रतिशत के आधार पर कोई भी छूट, अ-ला-कार्टे के साथ-साथ बुके में चैनल की कुल सब्सक्रिप्शन पर आधारित होगी। यदि किसी वतरक द्वारा अ-ला-कार्टे में पेशकश किए जाने के अलावा एक बुके में चैनल की पेशकश की जाती है, तो प्रसारक द्वारा पे चैनल के अधिकतम खुदरा मूल्य पर प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली कोई छूट, सब्सक्राइबर्स की वास्तविक संख्या या एक महीने में दर्ज वास्तविक सब्सक्रिप्शन

प्रतिशत के आधार पर, अ-ला-कार्टे और बुके दोनों में चैनल की कुल सदस्यता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

23. एक सवाल उठ सकता है कि यदि पूरे बुके ने थ्रेशोल्ड सब्सक्रिप्शन स्तर प्राप्त नहीं किया है तो एक बुके में से एक या एक से अधिक टेली वजन चैनलों के लिए प्रोत्साहन के रूप में छूट की गणना कैसे की जाएगी। ऐसे मामलों में, संबंधित बुके में टेली वजन चैनल के निवल मूल्य की गणना करके एक टेली वजन चैनल की संबंधित कीमत, जिसने सब्सक्रिप्शन सीमा (संयुक्त रूप से अ-ला-कार्टे आधार पर प्राप्त सब्सक्रिप्शन की गणना के साथ-साथ किसी बुके के हिस्से के रूप में) प्राप्त कर ली है, की गणना की जा सकती है।
24. प्राधिकरण प्रसारकों द्वारा दी जा रही छूट तथा बाजार पर इसके प्रभाव पर कड़ी नजर रखना जारी रखेगा, और यदि आवश्यक हो तो आगे उपयुक्त उपाय कर सकता है।
25. संबंधित प्रावधानों में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं।
26. प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए नए वनियामक ढांचे से संबंधित मुद्दों पर परामर्श पत्र दिनांक 7 मई 2022 पर, हितधारकों की समिति ने भादू वप्रा द्वारा भवष्य में वचार के लिए अन्य मुद्दों को भी सूचीबद्ध किया है जिसमें बुके के लिए डीपीओ को अतिरिक्त पंद्रह (15%) प्रतिशत प्रोत्साहन की अनुमति देना शामिल है, जैसा कि अ-ला-कार्टे चैनल के लिए प्रदान किया गया है। इसी तरह, परामर्श प्रक्रिया के दौरान, भादू वप्रा को इंटरकनेक्शन वनियमन 2017 (यथासंशोधित) से संबंधित अन्य मुद्दों पर भादू वप्रा के वचार के लिए सुझाव प्राप्त हुए, जिसमें कैरिज शुल्क की सीमा को हटाना, समाप्ति सीमा को हटाना आदि शामिल हैं। भादू वप्रा ने सुझावों को नोट कर लिया है और जरूरत पड़ने पर आगे उपयुक्त उपाय कर सकता है।
